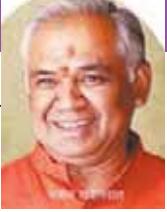


सामाजिक

राजीव खंडेलाल



(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैठक सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

विधान के तीन स्तरों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका की 'माननीय न्यायालय' का काम 'सिर्फ और सिर्फ' 'न्याय' देने का ही होता है। 'न्याय' देते समय न्यायालय को सिर्फ न्याय देने पर ही ध्यान केन्द्रित करना होता है। न्यायालय के आस-पास विद्यालय 'परिसर' से लेकर, बाहर कर्य परिवर्तनों, घटनाक्रम चल रहा है, उससे प्रभावित हुए बिना सिर्फ न्यायालय को समर्पण प्रस्तुत रिकॉर्ड (केस डायरी) पर उल्लेख तथ्यों की न्यायिक समीक्षा का माननीय न्यायालय 'न्यायिक निर्णय' देते हैं। न्याय की यह आदर्शी स्थिति है। न्यायालय का निर्णय किस पक्ष के पक्ष में है, हार-जीत में है, और निर्णय का समाज या देश के अन्य तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे उम्मत होकर ही, डर बिना ही निष्पक्ष व निषेच होकर माननीय न्यायालय निर्णय देते हैं। यही वातावरक न्याय है। यथा 'न्याय न क्यायी ऊपर, पंच न होते बिकास।'

संतुलन का परसेशन

माननीय उच्चतम न्यायालय के पिछले कुछ न्यायिक निर्णयों में कहीं न कहीं न्यायालय का 'प्रयास' ('स्वाभाविक अथवा अतिरिक्त') 'न्याय' के साथ दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास होता हुआ दिखता है। तथापि निर्णय 'न्यायिक' ही होते हैं। इस हेतु जरूरत पड़ने पर न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त असीमित विशेषाधिकार का भी सहारा लेती है। सामान्य न्यायालय के समाने दो ही पक्ष होते हैं, जो अपना-अपना पक्ष खटकते हैं। जिनके बीच ही निर्णय का तराजू का काटा घूमता है। तीसरा पक्ष वह होता है, जो न्यायिक निर्णय के परिणाम के आकलन का पक्षपात पूर्ण हुए बिना निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करता है, जिससे न्यायालय को न तो कोई लेना-देना होता है और न वीं इससे उसके 'स्वास्थ्य' पर कोई प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ समय से कुछ न्यायिक निर्णयों से बनते उक्त परसेशन 'संतुलन' बनाने को बल सा मिल रहा है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बन



इ स आम चुनाव में ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि से मोदी बनाम प्रतिपक्षी दल के बीच सत्ता संघर्ष का दौर चल रहा हो। इसके चलते आम नारिकों की जरूरतों में भाग्याता तो एक मात्रम् मारहै, जिसे समर्थन देकर मोदी का चयन किया जा सकता है। निश्चित रूप से नीति और सिद्धांतों के आधार पर दलीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र में लोकतंत्र की साथकता के प्रबल पक्षधर वर्गों के लिए यह चिता का विषय हो सकता है। अद्यता सावल यह है कि देश के लोकतंत्र में आखिर ऐसी कौन से कारण रहे जिसके चलते व्यक्ति विशेष को संस्कारण करते हुए एक व्यक्ति विशेष पर आधारित लोकतंत्र का परिदृश्य दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि भाजपा के प्रचार-प्रसार में भी

इस संदर्भ में जरा और गहराई में जाए तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता प्रसिद्धि के पश्चात दशकों तक कांग्रेस द्वारा व्यक्ति एवं परिवार विशेष पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हुए सत्तापक्ष की राजनीति की गई।

शिवेश प्रताप

लेखक तकनीकी प्रबंध

सलाहकार हैं।



यहे कुछ समय से तमाम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तों को ध्वना होता रहा है। यहीं दूसरी ओर भारत का प्रतिपक्षी दल के बीच अपेक्षाओं से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इसी के फलस्वरूप पूरी दुनिया अब भारत को निविवाद रूप से सबसे तेजी से प्रतिष्ठित करने वाली अर्थव्यवस्था मान चुकी है। इसी क्रम में भारत विश्व की पांचवां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद तेजी से विशेष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। परंतु इसी के साथ अपने प्रतिस्पर्धी एवं पद्धतियों देश चीन के साथ अपनी तुलना करने पर हमें कुछ कठोर यथार्थ का भी सामना करना पड़ता है। आज नहीं तो कल वैधिक मंच पर चीन को पछाड़ा के लिए हमें ऐसे कठोर यथार्थ को स्वीकार करते हुए इस समय देखने के त्रैयों के बालक बढ़ते हुए और अपने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ हम चीन से पीछे रह गए हैं।

एक और जीवंत काम का प्रति कैपिटा इनकम 12000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है वहीं दूसरी ओर भारत का प्रति कैपिटा इनकम मात्र 2200 अमेरिकी डॉलर है। एक तरफ चीन ने अपने देश से गरीबी का उम्मतन कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर भारत में गरीबी एक व्यक्ति का प्रस्तुत है। देश की आजाती के समय भारत की विश्वित चीन से काफी बेहतर थी, परंतु भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में हुई कुछ भारी गतिशीलता के कारण हमें देश की विशेष ध्यान देने से बदला जाता है। यह चुनौतियों के क्रम में देश की कुछ कठिन चुनौतियों के स्थायी और ठोस समाधान की कर आगे बढ़ना होगा। आज इन्हीं चुनौतियों और समाधानों की चर्चा इस लेख में की जा रही है।

करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा: अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर देश अपने आयात एवं नियंत

न्यायालय के निर्णयों में 'न्याय' के साथ 'संतुलन' का भी 'भाव' दिखता है?

संजय सिंह का जमानत आदेश

इसी संदर्भ में अभी ताजा उद्घारण आप पार्टी के संसद संजय सिंह के विश्वरूप प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई "पीएमएलए" का नाम के अंतर्गत शराब घोटाले से जुड़े मनी लांडिंग में की गई कार्रवाई के तहत की गई गिरियालय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय सिंह को देखा गया विरोधी को जमानत के निर्णय है। चौके आरोपी को जमानत मिली, इसीलिए उसके साथ न्याय हुआ, आरोपी की यह सोच स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर अधियोजन पक्ष जिसने आरोपी के विश्वरूप गिरफतारी की कार्रवाई की बाबजूद जमानत का विरोध और अधियोजन पक्ष के विश्वरूप गिरफतारी के बाबजूद जमानत का विरोध नहीं किया, तब भी यह कहा जाता है कि जमानत का विरोध नहीं किया, जो सामान्य रूप से अन्य प्रकरणों में इ.डी. अभी तक करता चला आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत मोदी सरकार के कार्रवाई की कार्रवाई की बाबजूद जमानत का विरोध नहीं किया, अभियोजन पक्ष की गई गिरियालय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय सिंह को जमानत देखा गया है।

ई.डी. द्वारा संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं

सबसे महत्वपूर्ण गैर करने वाली बात यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने संतुलन बनाने का प्रयास

तो रिकॉर्ड पर लाई है। कृपया यह ध्यान में रखिये कि यदि हमने खामियों पाई तो धारा 45 के अंतर्गत हम यह रिकॉर्ड करेंगे कि अपराध नहीं किया है, जो आपके लिए नुकसानदेह होकर उसका असर द्वायल की सुनवाई पर होगा। इस प्रकार एक तह पर उच्चतम न्यायालय ने एक

विकल्प देकर ई.डी. को अपलक्ष रूप से मजबूर किया कि वह जमानत का विरोध न करे। अन्यथा उनके खिलाफ आदेश परित कर जमानत दे दी जायेगी।

चंडीगढ़ मेयर का चुनाव

इसी तरह का चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के बोट का डाका सरे आम हुआ। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। उच्च न्यायालय के अंतर्मिस सहयोगी देने के इंकार के अंतर्मिस आदेश के विश्वरूप अपील दायर की गई थी। तब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जगह विवरण के बाबजूद जमानत को विरोध करने के लिए दूसरी रूप से स्पष्ट रूप से धांधली होते हुए दिखाए गए।

नहीं अंतर्मिस आदेश को किये गये? परंतु दुर्दायिक उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट तरंत उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित नहीं किया, बल्कि सरकार को नोटिस देते हुए 15 दिन बाद को सुनवाई निश्चित की गई। तपत्य तपत्य सिर्फ स्पष्ट नावन आवेदन पर आदेश परित करने की बजाए पूर्ण मामले को गुण-दोष के आधार पर न केवल चुनाव अवधि घोषित कर दिया, बल्कि हारे हुए उम्मीदवार को जाता हुआ भी घोषित कर दिया, जो वाचिकाकर्ता की मांग ही नहीं थी। इससे न्याय के साथ-साथ यह दिखाए गए संतुलन बनाये रखने का परसेशन बना, एसा इंकार किया गया है कि विवरण के बाबजूद भी एक अद्यतन नहीं होता है। आजकल जमानत नहीं रखता कि आदेश देने का प्रयास हुआ।

ही उलझ कर रह गई है। यदि कांग्रेस द्वारा बीते समय में यह परिवारी नहीं डाली गई होती तो देश का जागृत जनमत भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में भारी भरी नहीं रहता था, ब्याकों इसके बाबजूद उस अवधि घोषित करने के लिए भाजपा को जागृत जनमत नहीं रहती थी। इससे न्याय के साथ-साथ यह दिखाए गए संतुलन बनाये रखने का परसेशन बना, एसा कहने वाले को गलत नहीं कहा जा सकता है।

करते हुए देखकर तथाकथित 'न्याय' की दुर्वाई के साथ अस्तित्व को बाजाने की दिशा में कड़ा संचार करती दिखाई दे रही है।

अन्यथा भाजपा को ताल-चलन, चिंतन और व्यवहार ऐसा कदापि नहीं रहा कि सिद्धांतों पर आधारित यह दल विस्तीर्णी भी प्रकार की व्यक्तिवादी मानसिकता से प्रभावित रहा है। इस समय देश-प्रदेश की परिस्थिति ही कछुपी ऐसी है कि कांग्रेस को शिक्षित करने के लिए उसके ही दावे में लेकर व्यक्तिवाद की घुसपैठ के लिए भाजपा को करती जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

